

45

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2770-एक/2015 - विरुद्ध - आदेश
दिनांक - 17-7-2015 - पारित द्वारा - तहसीलदार जबलपुर --
प्रकरण कमांक 80 बी-121/2014-15

डा०शिव प्रसाद यादव पुत्र रामस्वरूप यादव
निवासी वाटर वर्क्स रोड 2285/2 भौंगाव्दार
जबलपुर मध्य प्रदेश
विरुद्ध

--- आवेदक

कु०अनामिका गुप्ता पुत्री पन्नालाल गुप्ता
बेलबाग तिराहा जबलपुर मध्य प्रदेश

--- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनुरोग तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अतुल ताम्रकार)

आ दे श

(आज दिनांक ३-10-2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 80 बी-121/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-15 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

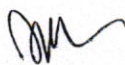
2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार जबलपुर कंट के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार कंट जबलपुर ने प्रकरण कमांक 80/बी-121/2014-15 पंजीबद्ध कर आवेदक को सुनवाई हेतु

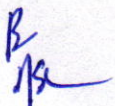
R
na

आहुत किया। आवेदक ने उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रदान कर प्रकरण की प्रचलनशील पर आपत्ति दर्ज कराई। तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-15 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत ही गई है।

3/ निगरानी में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने लेखी तर्क प्रस्तुत किये हैं। लेखी तर्कों के साथ तहसीलदार केंट जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 80/बी-121/2014-15 का अवलोकन किया गया।

4/ लेखी बहस एवं तहसीलदार केंट जबलपुर, के प्रकरण क्रमांक 80/बी-121/2014-15 अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 6-4-15 प्रस्तुत कर बताया है कि ग्राम सीतापुर स्थित खसरा क्रमांक 196 रकबा 1600 वर्गफुट भूमि उसके द्वारा हेमकुमार महावर पुत्र स्व.बेनीप्रसाद से कय की है, जब तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-1-13 के पालन में जब दिनांक 25-1-13 को इस भूखंड का सीमांकन कराया गया, सीमांकन के दौरान आवेदक अन्य लोगों के साथ आ गया और कहने लगा कि मैंने इस भूखंड पर कब्जा कर लिया है भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालूंगा। सीमांकन उपरांत तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 7-2-14 से निर्णय देकर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। निगरानी मेमो में मुख्य आधार यह लिया गया है कि धारा 250 का आवेदन कब्जे के 2 वर्ष के भीतर देना चाहिये जो 2 वर्ष वाद दिया गया है इसलिये संहिता की धारा 250 के अंतर्गत दावा ग्राह्य योग्य एवं प्रचलन-योग्य नहीं है। प्रकरण में देखना है कि क्या अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 250 का दावा 2 वर्ष की अवधि वाद दिया गया है। तहसीलदार के प्रकरण में आये

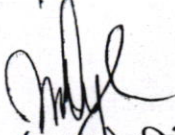




तथ्यों से ज्ञात होता है कि सीमांकन उपरांत तहसीलदार ने सीमांकन आदेश 7-2-14 को पारित कर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है तथा अनावेदक द्वारा धारा 250 का दावा तहसीलदार के समक्ष 6-4-15 को प्रस्तुत किया है जो दो वर्ष की अवधि के भीतर है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-15 से आवेदक के आपत्ति आवेदन पर लिया गया निर्णय उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80 बी-121/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-15 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

R
12


(एम०के०सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर